



EDU TERIA

E - D.N.A.

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 22 January 2026

27 साल, तीन मिशन और अंतरिक्ष में 608 दिन गुजारे | संन्यास | सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी का रिकार्ड भी

सुनीता विलियम्स 60 साल बेमिसाल, नासा को कहा अलविदा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों तक फंसे रहे दो अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल नासा की सुनीता विलियम्स सेवानिवृत्त हो गई हैं। नीसेना को पूर्व कप्तान विलियम्स (60) ने नासा में 27 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं दीं और अंतरिक्ष स्टेशन के तीन मिशन में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में गुजारे। उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी (स्पेसवाक) का रिकार्ड भी बनाया। उन्होंने कुल 62 घंटे अंतरिक्ष में चहलकदमी की।

अमेरिका को अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को बताया कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सेवानिवृत्ति का आदेश पिछले साल दिसंबर के अंत से



बयान में विलियम्स के हवाले से कहा गया कि जो कोई भी मुझे जानता है, उसे पता है कि अंतरिक्ष मेरा सबसे पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में सेवाएं देना और अंतरिक्ष में तीन बार उड़ान भरने का अवसर मिलना मेरे लिए अविश्वसनीय सम्मान रहा है। नासा में 27 साल का मेरा करियर अद्भुत रहा और यह मुख्य रूप से मेरे सहकर्मियों से मिले अत्यधिक प्रेम एवं समर्थन की वजह से संभव हो पाया।

प्रभावी हो गया।

बोइंग की कैस्पल परीक्षण उड़ान के दौरान विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में फंसे रहे युव विलमोर ने पिछले साल गर्मियों में नासा छोड़ दिया था। विलियम्स और विलमोर को 2024 में अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था और वे बोइंग के गए 'स्टारलाइनर' कैस्पल से उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उनका मिशन केवल एक

सप्ताह का था लेकिन स्टारलाइनर में आई दिक्कतों के कारण यह नौ महीने से भी लंबा खिंच गया। वे अंततः पिछले साल मार्च में पृथ्वी पर लौटे। नासा के 'राष्ट्र प्रशासक जैरेड आइवर्कमैन ने विलियम्स को 'अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में 'अग्रणी' बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि 'आपकी इस शानदार योगदान पर बधाई। बोइंग का अगला स्टारलाइनर मिशन

अंतरिक्ष स्टेशन तक मनुष्यों को नहीं, केवल माल को लेकर जाएगा। नासा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी को भी कैस्पल से अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसके थ्रस्टर और अन्य सभी समस्याओं को सुलझा लिए जाएं। यह परीक्षण उड़ान इस वर्ष बाद में होगी।

विलियम्स इस समय भारत दौर पर हैं। उन्होंने मंगलवार दोपहर को यहां अमेरिकी केंद्र में आयोजित एक संवाद सत्र में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में स्थल पर 'नजर सितारों पर, पैर जमीन पर' शीर्षक वाले पोस्टर लगाए गए थे जिनमें विलियम्स को 'नासा की सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नीसेना को सेवानिवृत्त कप्तान' के रूप में चर्चित किया गया था। उन्होंने संवाद के दौरान उस समय के अपने अनुभवों को भी साझा किया जब वह अंतरिक्ष में फंस गई थीं।

अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में बलिदान हुए ठाकुर रोशन सिंह



ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 1892 में आज ही वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। कुशल पहलवान और निशानेबाज के रूप में पहचान रखने वाले रोशन सिंह को उनके माता-पिता ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। रिहा होने के बाद क्रांतिकारी संगठन एचएसआरए में शामिल होकर सदस्यों को निशानेबाजी सिखाने लगे। 1924 में क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए पीलीभीत के बमरौली गांव में सूदखोर व्यापारी के यहां छाका डाला। इसी घटना को आधार बनाकर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 19 दिसंबर, 1927 को फांसी दे दी।



ग्रासामाशेल को 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

सम्मान

नई दिल्ली, एजेंसी। अफ्रीकी राजनेता, समाजसेवी व मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को 2025 के इंदिरा गांधी शांति, निस्स्त्रीकरण और विकास पुरस्कार' के लिए चुना गया।

अंतरराष्ट्रीय जूरी को अध्यक्षता भारत के पूर्व एनएसए/शिवशंकर मेनन कर रहे हैं। माशेल का पूरा जीवन मानवाधिकारों की रक्षा और कम-जोर वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित रहा है। उनका लक्ष्य हमेशा एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करना रहा है। ग्रासा को 1997 में संयुक्त



संयुक्त राष्ट्र का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार भी मिल चुका है

राष्ट्र का नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार और ब्रिटेन का मानद डेम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला। ग्रासा का जन्म 17 अक्टूबर, 1945 को मोजाम्बिक के एक गांव में हुआ था। बाद में लिस्बन विवि में छात्रवृत्ति प्राप्त की। वही उनके भीतर स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले ने रूसी क्रांति को जन्म दिया

1905 में आज ही रूसी सैनिकों ने श्रमिकों के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की थी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अधिकारियों का उद्देश्य जुलूस को विंटर पैलेस तक पहुंचने से रोकना था। इस 'रुकनी रविवार नरसंहार' ने 1905 की रूसी क्रांति को जन्म दिया।।



मतदाता जागरूकता में नवाचार के लिए पटना को मिला पुरस्कार

विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्यों के लिए पांच जिलों को मिलेगा सम्मान

उपलब्धि 1

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विधानसभा चुनाव-2025 में अलग-अलग कार्यों में बेहतर प्रदर्शन वाले पांच जिलों को पुरस्कार, भूमिका, पटना, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर जिलों को पुरस्कार के लिए किया गया है। पटना विधानसभा चुनाव 2025 में इन जिलों के निर्वाचन प्रशासकों को 25 जनवरी को 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पहिले स्थान में सम्मानित किया जाएगा।



विनोद सिंह मुजफ्फरपुर, कुन्दन कुमार पटना, विनोद सिंह मुजफ्फरपुर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं मानवजीन सिंह हिल्लन ईओ के डीआईजी भी होंगे सम्मानित

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विधानसभा चुनाव-2025 में अलग-अलग कार्यों में बेहतर प्रदर्शन वाले पांच जिलों को पुरस्कार, भूमिका, पटना, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर जिलों को पुरस्कार के लिए किया गया है। पटना विधानसभा चुनाव 2025 में इन जिलों के निर्वाचन प्रशासकों को 25 जनवरी को 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पहिले स्थान में सम्मानित किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन, तत्कालीन एडीओ कुन्दन कुमार और ईओ के डीआईजी मानवजीन सिंह हिल्लन को चुना गया है। इनमें भी 25 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। इनके साथ ही, सीईओ कार्यालय को सोशल मीडिया टीम एवं अन्य मीडिया संस्थानों को भी सम्मानित किया जाएगा। 19 वें संवैधानिक निर्वाचन के अग्र संचालक भास्कर कुमार सिंह ने सभी संवैधानिक निर्वाचनों के निर्वाचकों पर अग्र अभिनवांकों से 24 जनवरी को ही नई दिल्ली स्थित मानवजीन सेंटर में उपस्थित होने का अनुरोध किया है। अग्रोपेन ने कहा है कि 24 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली के लिए उपास्थित होना अनिवार्य है। साथ ही अग्रोपेन ने अग्रार्थ द्वाारा कहे जाने वाले प्रदासिकार्यों के द्वारा कई सुचनाएं भी मांगी हैं।

उत्तर बिहार बिजली कंपनी सर्वश्रेष्ठ, स्वर्ण पुरस्कार मिला

उपलब्धि 2

केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा रक्षित को रजत पुरस्कार के रूप में सर्वश्रेष्ठ बिजली कंपनी के रूप में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार की बिजली विद्युत कंपनी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार (एनबीडीसी) के रूप में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अर्थव्यवस्था विभाग के अध्यक्ष एमएसएम (एनबीडीसी) ने बिहार के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अर्थव्यवस्था विभाग के अध्यक्ष एमएसएम (एनबीडीसी) ने बिहार के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अर्थव्यवस्था विभाग के अध्यक्ष एमएसएम (एनबीडीसी) ने बिहार के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है।

तैयारी

सोलर से बिजली का होगा उत्पादन, दिन में सोलर से बिजली उत्पादित कर उसे बैटरी के माध्यम से शाम को पीक आवर में आपूर्ति की जाएगी

बसौनी में एक हजार मेगावाट आवर का बिजली घर बनेगा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बेगूसराय के बसौनी में पचास बिजली घर बनाने। दिन में सोलर से बिजली उत्पादित कर उसे बैटरी के माध्यम से शाम को पीक आवर में आपूर्ति की जाएगी। बैटरी इनजीनरी स्टोर सिस्टम (बीईएस) विकसित करने की जिम्मेदारी एनटीपीसी को दी गई है।

मंजूर 2000 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए बावलिहोटी गैस फीडिंग की स्वीकृति का निर्माण किया था। उनका तर्क था कि बैटरी स्टोर से बिजली को संचयित कर लिया जा सकेगा। इसी प्रकार चुनाव प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन पर भूमिका, मतदाता जागरूकता में नवाचार अग्रोपेन के लिए पटना, अग्रार्थ द्वाारा कहे जाने वाले प्रदासिकार्यों के द्वारा कई सुचनाएं भी मांगी हैं।

16 माह में बिजली घर का निर्माण पूरा होगा, एनटीपीसी को निविदा जारी। 02 सी 50 मेगावाट बिजली घर बिनेगा बिहार को। कजरार में पहले से चल रही परियोजना लखीसराय के कजरार में इस तरह की एक परियोजना चालू है। दूसरे चरण के तहत कजरार में दूसरी इकाई बनाई जा रही है। जो इस साल चालू हो जाएगा। कंपनी का मानना है कि कुल बिजली आपूर्ति में एक तिहाई से अधिक अक्षय ऊर्जा का होना जरूरी है। ऐसे में बसौनी में बिजली घर बनने से उस कोटा को पूरा करने में सहायता मिलेगी और बिहार को ऊर्जा नहीं देना होगा।

किसानों की आय बढ़ाने पर तेजी से हो रहा काम: सीएम

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर तेजी से काम किया है।

पीएम किसान सम्मान के लिए 29 लाख किसानों का ही निर्बंधन विशेष अभियान में सिर्फ एक तिहाई किसानों के आईडी बने

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने पर तेजी से काम किया है।

सुखद | केंद्रीय जल आयोग ने योजना को हरी झंडी दी, शुरुआत में छह जलाशयों को फायदा होगा

बिहार के जलाशयों में गंगाजल भेजने को मंजूरी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के जलाशयों को संकट से बचाने और इसके लिए गंगाजल आपूर्ति की योजना को केन्द्र की हरी झंडी मिल गयी है। केन्द्रीय जल आयोग ने योजना के पीपीआर को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में राज्य के 23 जलाशयों में से छह जलाशयों को गंगाजल की आपूर्ति होगी। दो से तीन माह में इस योजना का डीपीआर भी बन जाएगा।

132 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा

पहले चरण में यहाँ काम बासकुंड, लखीसराय, भोजपुर, जमुई, अंजन, जलकुंड, मुंगेर, गरीह, जमुई। 02 से तीन माह में योजना का डीपीआर भी तैयार हो जाएगा। इससे पहले चरण में बासकुंड, अमृत श्रृंखंडी, जलकुंड, भोजपुर, गरीह को गंगाजल मिलेगा। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण को तैयारी की जाएगी। इस योजना के तहत मानसून अर्थात् गंगाजल को पाइप के माध्यम से दक्षिण बिहार के जलाशयों तक पहुंचा जाएगा। इसके लिए प्रारंभ में 132 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन स्थापित होगी।

पांच बड़े लाभ

- 1. जलाशयों में सालों भर पानी रहेगा
2. बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी
3. गंगाजल की बाढ़ों से रक्षा होगी
4. भूजल स्तर में सुधार होगा
5. जलस्रोतों स्थिति बेहतर होगी

66 सूखे के जलाशयों को सुखे से बचाने की कार्रवाई योजना बनायी गई है। मानसून अर्थात् गंगाजल को जलाशयों तक पहुंचाने से इनका संकट दूर होगा। - विद्युत धारा, जल संसाधन मंत्री

इससे नवादा, लखीसराय, जमुई और मुंगेर जिलों को सुखे से भी निजात मिलेगी। साथ ही सिंचाई के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। जल संसाधन विभाग योजना के कार्यान्वयन में जुट गया है।

NATIONAL

मोदी कैबिनेट ने लिये दो बड़े फैसले, अटल पेंशन योजना का किया विस्तार

नई दिल्ली, (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में आज दो अहम और दूरगामी फैसले लिए गए। जिसका सीधा असर देश के करोड़ों मजदूरों के हितों में और छोटे उद्योगों पर पड़ेगा। एक और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा देने वाली अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए स्मॉल इन्टरप्राइज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता मंजूर की गई है।

कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को आगे बढ़ाने हुए इसके प्रचार प्रसार, धमना निर्माण और विकासवाक्य गतिविधियों के लिए सरकारी सहयोग जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही योजना को टिकाऊ बनाए रखने के लिए पिप फंडिंग को व्यवस्था भी जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि वर्ष 2015 में शुरू हुई यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी देती है। जनवरी

2026 तक इस योजना से 8 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। सरकार का मानना है कि निरंतर सहयोग से असंगठित क्षेत्र के और अधिक श्रमिकों तक इसका लाभ पहुंचेगा और देश एक पेंशनयुक्त समाज की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा।

वहीं दूसरे बड़े फैसले के तहत स्मॉल इन्टरप्राइज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी तीन चरणों में दी जाएगी। इसका उद्देश्य बैंक की पूंजीगत स्थिति को मजबूत करना और एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र को अधिक ध्यान उपलब्ध कराना है। इस पूंजी निवेश के बाद वर्ष 2028 तक लगभग 25 लाख 74 हजार नए एम्प्लॉयमेंट लाभांश जुड़ने की उम्मीद है। मौजूदा औसत के अनुसार इससे करीब 1 करोड़ 12 लाख नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। सरकार के अनुसार मजबूत पूंजी आधार से बैंक सस्ती दरों पर संसाधन जुटा सकेगा और छोटे उद्योगों को प्रतियोगी लागत पर ध्यान मिलेगा। देखा जाये तो आज के ये दोनों फैसले जनहित और दीर्घकालिक आर्थिक प्रसूक्षा के रूढ़ में बंधे हैं। अटल पेंशन योजना का विस्तार यह स्वीकार

एमएसएमई को सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने का रास्ता भी किया साफ



करता है कि भारत की अस्सी अर्थव्यवस्था आज भी असंगठित क्षेत्र के कंधों पर टिकी है। विस्थापित, परेश, कामगार, रेटर्न पट्टी वाले, खेत मजदूर या छोटे कारीगर, इनके लिए बुढ़ाया अस्तर अभावयता का दूसरा नाम रहा है। सरकार द्वारा इस योजना को 2030 तक बढ़ाना दरअसल इस वर्ग को यह भरोसा देना है कि काम करने की उम्र बीत जाने के बाद भी जीवन की गरिमा बनी रहेगी।

यह फैसला केवल पेंशन तक सीमित नहीं है। प्रचार और धमना निर्माण पर जोर बढ़ाकर देना है कि सरकार चाहती है कि ऑफिस चर्क में खड़ा व्यक्ति भी विदेशी सुरक्षा की भासा समझे। जब करोड़ों लोग नियमित बचत और पेंशन व्यवस्था से जुड़ने हैं तो वह देश को सामाजिक सुरक्षा के मजबूत ढांचे की ओर ले जाता है। विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब विकास का फल सिर्फ वरिष्ठन पीढ़ी ही नहीं बल्कि भविष्य की युवा पीढ़ी तक भी पहुंचे। उभर, स्मॉल इन्टरप्राइज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई इक्विटी सहायता भारतीय अर्थव्यवस्था की षडकुल काहे जाने वाले

एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा देने वाला कदम है। छोटे उद्योग केवल उत्पादन के केंद्र नहीं होते बल्कि रोजगार के सबसे बड़े स्रोत भी होते हैं। जब बैंक की पूंजी मजबूत होगी तो वह जोशिम उद्यमों में सक्षम होगा और छोटे उद्यमियों तक बिना जमानत डिफिडेंस अड्डा पहुंचा सकेगा। इससे स्टार्टअप से लेकर पारंपरिक कुटीर उद्योग तक सभी को फायदा मिलेगा। इस निर्णय का सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ेगा। अनुमानित एक करोड़ से अधिक नए रोजगार केवल ऑफर नहीं हैं बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिरता का आधार बन सकते हैं। सस्ती और सारग पर विचार वाली पूंजी से छोटे उद्योग न केवल टिके बल्कि विस्तार भी करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा, पलायन घटेगा और ग्रामीण व अर्धनगरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बहरहाल, इन दोनों फैसलों को सफल रखकर देखें तो जो व्यक्ति उभर कर आती है वह है एक तरफ बुढ़ाया की सुरक्षा की गारंटी और दूसरी तरफ युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार। यह नीति वरिष्ठन और भविष्य दोनों को साधने की कोशिश है।

तैयारी

सातों टीलों पर होगी खोदाई, सबसे पहले टीला एक पर होगा काम शुरू, खोदाई का शुभारंभ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक वाईएस रावत करेंगे

राखीगढ़ी में आज से होगी खोदाई, नगर स्वरूप का लगाएंगे पता

संस, जामरग, नासर्द (हंसी) : आइकानिक साइट राखीगढ़ी में अलग-अलग समय पर सभी सातों टीलों पर खोदाई होती रही है। इस बार नगर का स्वरूप जानने के लिए खोदाई होगी। सभी टीलों के बाहरी किनारों पर खोदाई करके यह पता लगाया जाएगा कि इनका मुख्य द्वार कहाँ होता था और एक टीला का दूसरे से क्या संबंध होता था। इन टीलों को अलग-अलग करने वाले अंतर को भी देखा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले टीला नंबर एक पर खोदाई का शुभारंभ गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक वाईएस रावत करेंगे।

राखीगढ़ी में अब तक टीलों के बीच ही खोदाई का कार्य किया गया है। इस बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नए ढंग से सोच कर खोदाई करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। हजारों साल पहले उनके नीचे का आकार किस प्रकार का होता था। बाढ़ को रोकने के लिए दो लोग किस



राखीगढ़ी के टीले एक पर निरीक्षण करते हुए महानिदेशक वाई एस रावत व मनोज साक्सेना। जामरग

तकनीक से काम करके पानी रोकते थे। जंगली जानवरों और पशुओं से कैसे गांव या शहर की रक्षा की जाती थी। नगर की संरचना और उसका आकार कैसा था। सीमा के अंदर व बाहर का स्वरूप कैसा था। सीमा पर चहारदीवारी थी या नहीं। इन सभी

पहलुओं को खोजने के लिए टीलों के बाहरी क्षेत्र पर खोदाई की जाएगी। इन टीलों पर रहने वाले लोगों का ज्ञान भी एक दूसरे से मेल खाता था। आपस में व्यापार और लेन-देन भी किया जाता था। दख्खटी के किनारे पर बसा था

राखीगढ़ी राखीगढ़ी सरस्वती नदी की सहायक नदी दख्खटी के किनारे पर बसा था। नदी करीब दस हजार वर्ष पहले पूरे वेग से बहती थी। फिर उसमें धीरे-धीरे पानी कम होता गया और अंततः यह सूख गई। इस पर भी काम किया जा रहा है। टीलों के बीच में खोदाई से पता लगाया जाएगा कि इस नदी में जब बाढ़ आती होगी तो पानी इन टीलों के बीच में कहाँ से निकलता होगा।

दुनिया की महत्वपूर्ण साइट है राखीगढ़ी : राखीगढ़ी : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली के महानिदेशक वाईएस रावत ने बताया कि यह दुनिया की काफी महत्वपूर्ण साइट है। ऐसी साइट पर खोदाई करने का मौका कभी-कभी ही मिलता है। नए ढंग से सोचकर ही खोदाई करने की योजना तैयार की है। इस बार बाहरी क्षेत्र पर खोदाई की जाएगी। उस समय नगर का स्वरूप कैसा होता था, जैसा अब तक देखा नहीं गया को दुनिया के सामने लाया जाएगा।

भारत-पाक सीमा पर बीएसएफ चलाएगा 'आपरेशन सर्द हवा'

जास, जयपुर

राजस्थान से सटी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 22 से 29 जनवरी तक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) आपरेशन सर्द हवा चलाएगा। आपरेशन सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर एवं श्रीगंगानगर जिलों में चलाया जाएगा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ाने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलिंग भी करेंगे। जनवरी माह में तेज सर्द, घने कोहरे और कम दृश्यता का लाभ उठाकर सीमापार से घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों की आशंका हमेशा रहती है। ऐसे में बीएसएफ की ओर से प्रतिवर्ष जनवरी में गणतंत्र दिवस के आसपास आपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है।

जासकारी के अनुसार, 22 से 29 जनवरी तक तारबंदी के निकट जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यालयों एवं कार्यालयों में तैनात जवानों की सीमा पर तैनात किया जाएगा। जैसलमेर एवं

बीएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ाने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी करेंगे पेट्रोलिंग



बाड़मेर के रेगिस्तान में ऊंटों पर सवार होकर जवान पदचिन्हों की भारी की से जांच करेंगे। रेतीले टीलों में भी जवानों को तैनात किया जाएगा। सीमावर्ती जिलों में घने कोहरे को देखते हुए नाइट विजन कैमरों एवं थर्मल इमेजर का उपयोग भी बढ़ाया गया है। सीमावर्ती जिलों में बीएसएफ के साथ ही पुलिस भी गश्त तेज करेगी। बीएसएफ के जवानों एवं पुलिसकर्मियों की संयुक्त गश्त भी होगी। ज्ञात हो, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों व सैन्य ठिकानों का तबाह किया था।

EDITORIAL

Jansatta Page
Dainik Jagaran Page

ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे ऐसा क्या है, जिसके लिए ट्रंप पागल हो रहे हैं, सीक्रेट शहर का वो 'राज' जिसे दशकों तक दुनिया से छिपाया गया

17 जनवरी 2026 जब यूरोप में लोग सो रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनों को भी झटका दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फरमान जारी किया जिससे वाशिंगटन से लेकर ब्रूसेल्स तक हड़कंप मच गया। डॉनल्ड ट्रंप लिखते हैं कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड। ये सभी देश जो ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। पता नहीं किस इरादे से। यह खतरनाक स्थिति है। इसलिए जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और कुल खरीद के लिए डील नहीं हो जाती तब तक 1 फरवरी से इन पर 10% टेरिफ और 1 जून से 25% टेरिफ लगाता। डोनाल्ड ट्रंप नाटो के देशों पर टेरिफ लगा रहे थे। वैसे ही जैसे भारत पर लगाया था जब भारत ने उनकी बात नहीं मानी थी। ट्रंप का यह जो ऐलान था यह अचानक नहीं था। इसके पीछे इंगो फैक्टर था क्योंकि इन आठ देशों ने डॉनल्ड ट्रंप के इंगो को डेंट कर दिया था। वो टोकर मारी थी जो अंदर चुभ रही थी

आठ जंग रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत से क्या-क्या किया? वेनेजुएला में सेना उतार कर राष्ट्रपति को उड़वा लिया। ईरान पर हमले की धमकी दे दी। तमाम देशों पर नए टेरिफ लगाने की भी धमकी दे डाली। और अब ईरान में हालात सामान्य होने की बात कह के ग्रीनलैंड की तरफ रुख कर लिया। सेल्फ एक्सेन्स पीस प्रेसिडेंट ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन ये कहते हैं कि यूक्रेन पर हमारा नियंत्रण हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। क्योंकि नाटो हमारी दहलीज पर आया तो अमेरिका और पूरा पश्चिम चिल्लाता है कि यह तानाशाही है। रूस ने तो आक्रमण कर दिया। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन जब वही अमेरिका वही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर हमारा कब्जा हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चीन और रशिया वहां आ जाए। तो अमेरिका उसे स्ट्रेटजी बता रहा है, डील बता रहा है। दरअसल, ग्रीनलैंड की कहानी जो है वो सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं है। वो दुनिया के बदलते नियमों की है। वाशिंगटन से लेकर ब्रूसेल्स तक ट्रंप ने मचाया हड़कंप: 17 जनवरी 2026 जब यूरोप में लोग सो रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनों को भी झटका दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फरमान जारी किया जिससे वाशिंगटन से लेकर ब्रूसेल्स तक हड़कंप मच गया। डॉनल्ड ट्रंप लिखते हैं कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड। ये सभी देश जो ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। पता नहीं किस इरादे से। यह खतरनाक स्थिति है। इसलिए जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और कुल खरीद के लिए डील नहीं हो जाती तब तक 1 फरवरी से इन पर 10% टेरिफ और 1 जून से 25% टेरिफ लगाता। डोनाल्ड ट्रंप नाटो के देशों पर टेरिफ लगा रहे थे। वैसे ही जैसे भारत पर लगाया था जब भारत ने उनकी बात नहीं मानी थी। ट्रंप का यह जो ऐलान था यह अचानक नहीं था। इसके पीछे इंगो फैक्टर था क्योंकि इन आठ देशों ने डॉनल्ड ट्रंप के इंगो को डेंट कर दिया था। वो टोकर मारी थी जो अंदर चुभ रही थी। असल में अमेरिका ने जब ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जाने की शुरुआती धमकियां दी तो वही वो आठ यूरोपीय देश थे जिन्होंने डेनमार्क के साथ कहा कि हम खड़े रहेंगे। मजबूती से रहेंगे। ग्रीनलैंड में सेना भेजा तो ट्रंप ने निकाला टेरिफ वाला हथियार: यह मजबूती दिखाने के लिए नाटो के उस्तुलों का सम्मान करते हुए इन आठ देशों ने अपने सैनिक जो हैं वो ग्रीनलैंड भेज दिए। इनडायरेक्टली ये अमेरिका को एक बड़ा संदेश था कि ग्रीनलैंड अकेला नहीं है। हाथ मत लगाना। लेकिन



ट्रंप जो अपने इंगो के लिए जाने जाते हैं ना खाता ना वही जो हम सोच रहे हैं बस वही सही। उन्होंने इसे अपनी शान के खिलाफ मान लिया। 1 फरवरी से इन सभी आठ देशों के समानों पर 10% एक्स्ट्रा टेरिफ लगा दिया गया। धमकी दी गई कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के मन मुताबिक समझौता नहीं हुआ। यानी ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं सौंपा गया तो यह टेरिफ बढ़कर 25% कर दिया जाएगा। यह 25% किसी दूरमन देश पर नहीं लगाया गया। यह उन दोस्तों पर लगाया गया है जो पिछले 75 सालों से हर युद्ध में अमेरिका के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। कितना जरूरी है ग्रीनलैंड: ग्रीनलैंड का महत्व उसकी लोकेशन में निहित है। ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक रीजन के आठ देशों में से एक है। ऐसे तो यह डेनमार्क का हिस्सा है लेकिन ऑटोनॉमस टेरिटरी है यानी स्वायत्त क्षेत्र। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका है और बर्फ की भी 4 किमी मोटी परत है। लेकिन अब यह पिघल रही है। आर्कटिक रीजन बाकी दुनिया के मुकाबले चार गुना रम्यार से तप रहा है। करीब 26 लाख स्क्वायर किमी बर्फ गायब हो चुकी है। डाटा के मुताबिक इसी बर्फ के नीचे दुनिया की 30% अनएक्सप्लोर्ड गैस और 13% अनएक्सप्लोर्ड ऑयल यह छुपे हुए हैं। इसके अलावा यहां कोमती थालिए सोना, प्लैटिनम, जस्ता और लौ, अयरस्क, तांबा, सीसा, मोलिब्डेनम और टाइटैनिमय सह सब भी मौजूद बताए जाते हैं। इन सब यजहों से इस आइलैंड पर ट्रंप ही नहीं रूस और चीन की भी नजर बनी रहती है। शीत युद्ध के दौरान, ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूके गैप नाटो की समुद्री रणनीति का केंद्रीय तत्व था, जो अटलांटिक में प्रवेश करने वाली सोवियत पनडुबियों की निगरानी को संभव बनाता था। दशकों तक आर्कटिक एक जमे हुए बर्फ की तरह रहा- दूरस्थ, दुर्गम और लंबे समय तक चलने वाली प्रतिक्रिया से लगभग अप्रभावित। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन आर्कटिक को एक सक्रिय क्षेत्र में बदल रहा

है। पिघलती बर्फ नए समुद्री मार्ग खोल रही है। साथ ही, हाइपरसोनिक हथियारों, लंबी दूरी के सटीक प्रहार, अंतरिक्ष-आधारित सेंसर, मिसाइल रक्षा और समुद्रगत प्रणालियों में प्रगति दूरी को लगातार समेट रही है। ऐसे में ग्रीनलैंड हाथिये से खिसककर अग्रिम रणनीतिक क्षेत्र में बदल जाता है। जो दूरी कभी सुरक्षा देती थी, वह सिमट रही है; प्रतिक्रिया का समय घट रहा है; और अमेरिका मुख्यभूमि के लिए चेतावनी का अंतराल सिक्ड़ता जा रहा है। बर्फ के नीचे छिपा अरबों खरबों डॉलर का खजाना: आज की दुनिया तेल पर नहीं चिपस और बैट्रियों पर चलती है। आपका iPhone हो, टेल्सा कार हो या फिर F35 फाइटर जेट सबको चलने के लिए यह मिनरल्स चाहिए। फिलहाल इन पर चीन का राज है। अमेरिका जानता है कि भविष्य का तेल वही मिनरल्स है और यह खेल सिर्फ सरकार का नहीं बड़े-बड़े अरबपति जैसे बिल गेट्स, पीटर थील भी ग्रीनलैंड के खनिजों में पानी की तरह ऐसा बहा रहे हैं। कोबाल्ट मेटल्स जैसी कंपनियां वहां खुदाई की तैयारियां कर रही हैं। उन्हें पता है कि भविष्य का सोना यहीं छिपा है। बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जिसे पोलर सिल्व रोड कहा जा रहा है। जो जहाज एशिया से यूरोप जाने के लिए रिवज नहर का लंबा रास्ता लेते थे। वो भविष्य में ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेंगे। यह रास्ता दूरी को 40% तक कम कर देगा। ग्रीनलैंड जो चेक पोस्ट है जो आने वाले 100 सालों तक वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करेगा। भारत के उदाहरण से समझें। सियाचिन ग्लेशियर का कोई विशेष आर्थिक मूल्य नहीं है, उस पर भारी लॉजिस्टिक लागत भी आती है और वह अनुभवी सैनिकों के लिए भी अत्यंत दुर्गम है। इसके बावजूद भारत दशकों से सियाचिन पर कायम है। क्योंकि उसे खाली करने का अर्थ होगा पाकिस्तान को ऐसे भू-भाग पर कब्जा करने देना, जो भले ही आज सीमांत लगे, लेकिन भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। एक बार ऐसा इलाका हाथ से निकल जाए तो उसे वापस

हासिल करना कई गुना महंगा पड़ता है। इसलिए सियाचिन पर बने रहने का फैसला तात्कालिक सामरिक लाभ से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दूरदृष्टि से उपजा है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड भी कुछ ऐसा ही है। अमेरिका के सीक्रेट शहर की कहानी क्या है: क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे अमेरिका का एक सीक्रेट शहर आज भी दबा हुआ है। बात है 1960 के दशक की। शीत युद्ध अपने चरम पर था। उस चक कोल्ड वॉर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड में एक बेहद खुफिया मिशन चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट आइस बर्न। प्लान बेहद खतरनाक था। अमेरिका ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदकर एक पूरा शहर कैम संचुरी बसाना चाहता था। वहां 600 परमाणु मिसाइलें तैनात करने की योजना थी जो लगातार चलती रहती और सोवियत संघ के निशाने पर होती। अमेरिका ने वहां पर सिनेमा हॉल, चर्च और रहने की भी जगह बनाई थी। सब कुछ बर्फ के नीचे लेकिन कुदरत से कोई नहीं जोत पाया। ग्लेशियर की बर्फ खिसकने लगी और वो पूरा शहर दब गया। प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा। अब ग्लेशियर वापस से जब बर्फ पिघल रही है तो जहर के वावर आने का खतरा भी मंडरा रहा है। यही नहीं साल 1968 में अमेरिका का एक इ52 बम वर्षक विमान जिसमें चार हाइड्रोजन बम थे। ग्रीनलैंड में क्रैश हो गया। उस हादसे को ब्रोकन एरो कहा जाता है। ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड सुरक्षित नहीं है। लेकिन सच तो यह है। ग्रीनलैंड को सबसे ज्यादा खतरा खुद अमेरिका के प्रयोगों से हो रहा है। अब आगे क्या: अमेरिका की नीति नेटो देशों के साथ परंपरागत संबंध बनाए रखने की रही है। लेकिन वहां एक बड़े वर्ग की सोच थी कि यूरोपीय देशों में अनेक अमेरिकी नीतियों के साथ नहीं चलते, उसका विरोध करते हैं जबकि अमेरिकी सैन्य शक्ति से ही उनकी धाक है। उनका सवाल यह भी था कि जब सोवियत संघ खत्म होने के साथ उसके सैन्य हथियार समाप्त हो गए तो नाटो की आवश्यकता ही क्या है? ट्रंप नाटो को खत्म नहीं कर रहे, पर उनकी अगुआई में अमेरिका अपने हिस्सा से इसका संचालन सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर है। बहरहाल, इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के इस रुख और व्यवहार का विरोध करने वाले भी बढ़ी संख्या में हैं। बावजूद इसके, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें अमेरिका के प्रभुत्व और प्रभाव का पूरे विश्व को अहसास कराने और उसे आर्थिक व सामरिक रूप से पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने और दुनिया में अमेरिका को केंद्रित विश्व व्यवस्था का रास्ता तैयार करने वाला नेता माना जाएगा।

अमरजीत मौआर

भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती 'प्रति व्यक्ति आय को ऊंचे स्तर तक ले जाना'

दावोस, 21 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं, अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि यह 2028 या उससे भी पहले संभव है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के एक सत्र में यहां वैष्णव ने कहा कि चिंता का एकमात्र विषय अमीर देशों में कर्ज का पहाड़ और उनका भारत पर संभावित असर क्या होगा है।

गोपीनाथ ने कहा कि भारत के लिए चुनौती तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नहीं है बल्कि प्रति व्यक्ति आय को ऊंचे स्तर तक ले जाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि महंगाई में नरमी और मजबूत आर्थिक वृद्धि के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था अगले पांच वर्षों में वास्तविक रूप से छह-आठ फीसद और मौजूदा कीमतों पर 10-13 फीसद की दर से बढ़ती रहेगी। वैष्णव ने यहां संबोधित करते हुए अनुमति प्रक्रियाओं के सरलीकरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूरसंचार टावर स्थापित करने में लगने वाला औसत समय 270 दिनों से घटकर सात दिन रह गया है और 89 फीसद अनुमतियां अब तुरंत मिल रही हैं।

वैष्णव ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में परिवर्तनकारी बदलाव हुआ है जो सुविचारित, स्पष्ट रूप से परिभाषित और बेहतर क्रियान्वयन पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि यह चार स्तंभों भौतिक, डिजिटल एवं सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश,

भारतीय नेताओं का मजबूत आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण अनुकूल उपायों पर जोर

नई दिल्ली, 21 जनवरी (यूरो)।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में जहां वैश्विक नेता सुस्त आर्थिक वृद्धि और बढ़ते जलवायु जोखिमों पर चिंता जता रहे हैं, वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल देश की मजबूत वृद्धि दर और पर्यावरण अनुकूल उपायों को प्रमुखता से पेश कर रहा है। एक परिचय में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

उन्होंने सतत विकास और ग्रिड स्थिरता के लिए निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। जोशी ने बताया कि भारत ने डिजिटलीकरण और स्मार्ट मीटरिंग के जरिए अपने ग्रिड का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया है, जिसने व्यवस्था को मजबूत किया है और नागरिकों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे ही जल्द चौथी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, अब मुख्य आवश्यकता ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने की है। 'ग्रिड स्थिरता' का मतलब बिजली के नेटवर्क (ग्रिड) में उत्पादन (आपूर्ति) और खपत के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखना है। मंत्री ने कहा कि भारत निवेश पर शानदार रिटर्न प्रदान करता है, जिसे एक

स्थिर नियामक व्यवस्था और सुसंगत नीतियों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इन्हीं नीतियों ने भारत को एक 'नाजुक अर्थव्यवस्था' से बदलकर वैश्विक वृद्धि के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने में मदद की है। जोशी ने कहा कि कम गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए), निर्यात मुद्रास्फीति, बढ़ते उत्पादन और तेजी से सुधरते बुनियादी ढांचे के साथ भारत निवेश के लिए आकर्षक अवसर पेश कर रहा है। डारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के 42 फीसद खनिज संसाधन डारखंड में हैं, जो देश के विकास के लिए अनिवार्य हैं। उन्होंने संसाधनों की रक्षा के साथ-साथ राज्य में समृद्धि लाने पर जोर दिया। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, 'गुजरात बड़े पैमाने पर पर्यावरण अनुकूल उपायों का उदाहरण पेश करता है। इसने अपनी औद्योगिक क्षमता को संतुलित विकास और संसाधन दक्षता के माडल में बदल दिया है।' उन्होंने कहा कि गुजरात लंबे समय से भारत का विकास इजन रहा है, जो राष्ट्रीय जीडीपी, निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दे रहा है। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि भविष्य के लिए स्थिरता के हमारे चार प्रमुख स्तंभ हैं: पारिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिकता, व्यापार करने की गति, तीसरा, पर्यावरण अनुकूल रोजगार और कौशल में निवेश और नैतिकता निश्चितता एवं दक्षता।

समावेशी विकास, विनिर्माण एवं नवाचार और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर टिका है। वैष्णव ने कहा कि इन सभी को प्रौद्योगिकी मंच के साथ जोड़कर हमने ऐसा ढांचा तैयार किया है

जिससे अगले पांच वर्षों में भारत छह से आठ फीसद की वार्षिक वृद्धि, दो से चार फीसद की महंगाई और 10-13 फीसद की बाजार मूल्य आधारित वृद्धि हासिल करेगा।

मैक्रों ने ट्रंप की धमकी के जवाब में ईयू से व्यापार में बदलाव को लेकर विचार का आग्रह किया

ब्रसेल्स, 21 जनवरी (एपी)।

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से चिंतित यूरोपीय संघ, अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर विचार कर सकता है। यूरोपीय संघ (ईयू) अमेरिकी सामान पर भारी शुल्क से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सुझाए गए तरीकों को अपना सकता है। मैक्रों 'ईयू' एंटी-कोर्सिजन इंस्ट्रूमेंट (एसीआइ) को लागू करने का सुझाव दे रहे हैं। इसके तहत उन व्यक्तियों या संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो यूरोपीय संघ पर अनुचित दबाव डालते हुए जाते हैं।

इन प्रतिबंधों से यूरोपीय संघ के बाजारों तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच सीमित हो सकती है, उन्हें यूरोपीय संघ के सार्वजनिक निविदाओं में भाग लेने से भी रोका जा सकता है। इसके साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात में कमी आ सकती है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। एसीआइ की स्थापना यूरोपीय आयोग द्वारा 2021 में तब की गई थी जब चीन ने ताइवान के साथ लिथुआनिया के संबंधों को लेकर उससे व्यापार प्रतिबंधित कर दिया था। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। मैक्रों ने मंगलवार को दावोस में आग्रह किया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क यूरोपीय संघ को पहली बार अपने दबाव-रोधी तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी का असर रुपया 67 पैसे टूटकर 91.64 के रिकार्ड निचले स्तर पर

ननसाता यूरो नई दिल्ली, 21 जनवरी।

अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया बुधवार को 67 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 91.64 (अस्थायी) पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता और जोखिम लेने की धारणा कमजोर होने के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी के दबाव में रुपए में गिरावट आई। बाजार सूचों ने कहा कि रुपया 16 दिसंबर, 2025 को 91.14 के अपने पिछले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा था। इस महीने अब तक रुपये में 1.50 फीसद की गिरावट आई है।

उन्होंने कहा कि इस गिरावट का कारण बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता हो सकती है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड मुद्दे और संभावित शुल्क को लेकर यूरोप में बढ़ते तनाव, साथ ही घरेलू बाजार में नकारात्मक रुख ने निवेशकों की कारोबारी धारणा को और प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, रुपया 91.05 पर खुला और डालर के मुकाबले 91.74 के कारोबार के निचले स्तर पर आ गया। कारोबार के अंत में रुपया 91.64 (अस्थायी) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर से 67 पैसे कम था। एचडीएफसी

सिक्वोरिटीज के शोध विश्लेषक, दिलीप परमार के मुताबिक, 21 नवंबर, 2025 के बाद यह एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। मंगलवार को, रुपया सात पैसे टूटकर 90.97 पर बंद हुआ था।

कोटक महिंद्रा एएमसी के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम), अभिषेक बिसेन ने कहा कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर पूंजी के प्रवाह के दबाव का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक कारोबार पर असर डाल रहे हैं। वैश्विक तनाव में ग्रीनलैंड विवाद और वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण शामिल है। ग्रीनलैंड विवाद ने अमेरिका-यूरोप संबंधों को खराब किया है और इससे नाटो के ट्रटने का खतरा है। बिसेन ने कहा कि भारत के लिए, अमेरिका के साथ लंबित व्यापार समझौता एक अहम संतुलनकारी पहलू बना हुआ है, क्योंकि इसके होने से विस्थापित और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि साथ ही, जब तक भू-राजनीतिक जोखिम कम नहीं हो जाता और व्यापार समझौता नहीं हो जाता, तब तक रुपया बाहरी झटकों के प्रति कमजोर बना रह सकता है। हालांकि, मजबूत विदेशी मुद्रा निम्न स्तर पर बंद हुए, भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति को संभाल सकता है।

व्यापार समझौता एक अहम संतुलनकारी पहलू बना हुआ है, क्योंकि इसके होने से विस्थापित और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि साथ ही, जब तक भू-राजनीतिक जोखिम कम नहीं हो जाता और व्यापार समझौता नहीं हो जाता, तब तक रुपया बाहरी झटकों के प्रति कमजोर बना रह सकता है। हालांकि, मजबूत विदेशी मुद्रा निम्न स्तर पर बंद हुए, भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति को संभाल सकता है।

निवेशकों के पांच लाख करोड़ का नुकसान

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी बिकवाली देखने को मिली। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद निवेशकों की कमाई पर बड़ी चोट पड़ी और सिर्फ पहले कुछ घंटों के अंदर ही मार्केट से करीब 5 लाख करोड़ रुपए की दौलत साफ हो गई। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। इन तीन दिनों में निवेशकों के 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ग्लोबल टैशन, कमजोर घरेलू नतीजे, गिरता रुपया और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने मिलकर बाजार को बुरी तरह दबाव में डाल दिया।

वहीं, दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने, कमजोर संकेतों और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे सत्र में सूचकांक 271 अंक टूट गया जबकि निफ्टी में 75 अंक की गिरावट रही। कारोबारियों के मुताबिक, डालर के मुकाबले रुपए में कमजोरी और वित्तीय, बैंकिंग एवं उपग्रह से जुड़े शेयरों में बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बनाए रखा। हालांकि, निचले स्तर पर चुनिंदा शेयरों में खरीदारी आने से थोड़ा समर्थन मिला। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक भारी उतार-चढ़ाव के बाद 270.84 अंक वाली 0.33 फीसद गिरावट 81,909.63 अंक पर बंद हुआ।

सोना, चांदी के भाव नए शिखर पर

राष्ट्रीय राजधानी के सरका बाजार में बुधवार को सोना और चांदी नए शिखर पर पहुंच गए। सोने की कीमत करीब 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 3.34 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। अखिल भारतीय सरका संघ के अनुसार,

99.9 फीसद शुद्धता वाला सोना 6,500 रुपए वॉनो 4.24 फीसद बढ़कर 1,59,700 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया। मंगलवार को, सोने ने पहली बार देश की राजधानी में 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के महत्वपूर्ण स्तर को पार किया। स्थानीय

सरका बाजार में चांदी की कीमत में भी लगातार नौ दिन तेजी जारी रही। चांदी की कीमत 11,300 रुपए बढ़कर 3,34,300 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 20,400 रुपए बढ़कर 3,23,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्वोरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज), सीमित गांधी ने कहा कि सोने और चांदी ने बुधवार को नए रिकार्ड ऊंचाई को छुआ। लगातार सुरक्षित निवेश की मांग की रही।



शिक्षा में नवाचार की चुनौतियाँ

दावा किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और नवाचार के मामले में भारत तेजी से उभर रहा है। शोध कार्यों में भी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मगर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की राह अब भी कई तरह की चुनौतियों से घिरी है।

सुरेश सेठ

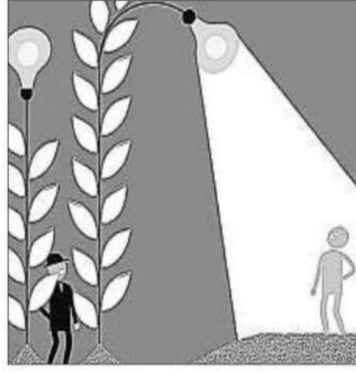
भा

रत में बदलाव और विकास को रफ्तार देने के लिए नवाचार एक अहम पहलू है। इस समय कृत्रिम मेधा के माध्यम से भारत सबसे अग्रणी होने का प्रयास कर रहा है। इंटरनेट की शक्ति को 6जी से आगे ले जाने की कोशिश हो रही है और हर पुराने तरीके को कृत्रिम मेधा की सहायता से बदलने की पहल हो रही है। दावा किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और नवाचार के मामले में भारत तेजी से उभर रहा है। शोध कार्यों में भी देश किसी से पीछे नहीं है। पेटेंट की बात की जाए तो इसके लिए उद्यम और प्रौद्योगिकी में हम लगातार नए अन्वेषण कर रहे हैं। पेटेंट मामले में भारत दुनिया में छठे स्थान पर पहुँच गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के मामलों में दावा किया जाता है कि हम शीर्ष देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। मगर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की राह अब भी कई तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है।

वैश्विक नवाचार में जो मुकाबला होता है, उसमें भारत ने लगातार अपनी बढ़त बनाई है और वह 90वें पायदान से तीसवें स्थान पर पहुँच गया है। भारत के भावी प्रौद्योगिकी मिशनों में भी इसका विस्तार करने और सार्वजनिक क्षेत्र में कृत्रिम मेधा के विकास का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसके लिए शिक्षा में जो परिवर्तन होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा परिसरों में जो नवाचार दिखाई देना चाहिए, वह भी नहीं दिखाई देता। निजी क्षेत्र ने विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में भारी निवेश किया है। पंजाब को ही लें। इस राज्य में तीन मुख्य विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय ज़रूर खुल गए हैं, लेकिन उनमें विद्यार्थियों की कमी तो है ही, वहीं सटीक पाठ्यक्रमों का अभाव भी नजर आता है। यहाँ कहीं नवाचार नहीं दिखाई देता है।

केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया था। इसमें देश की विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को एक साथ मिला कर सीधा रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी। अब इस अभियान में भी नवाचार की घोषणा शिक्षा मंत्रि ने की है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े सपने देखने के साथ भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में भी नई बुलंदियों को छूना चाहता है। वह अमेरिका या रूस के मुकाबले किसी भी तरह पीछे नहीं रहना चाहता। हालाँकि दूसरे क्षेत्रों में विकास की अब भी बहुत गुंजाइश है। वैसे मुद्दे की बात यह है कि शिक्षा के सभी पुराने ढर्रे अब बदले जाने चाहिए।

विज्ञान की समझ हर विद्यार्थी में हो, तभी शिक्षा में विकास के सपने पूरे हो सकेंगे। मगर इन सबके लिए पूंजी चाहिए। नीति आयोग यह कहता है कि कम से कम छह फीसद व्यय शिक्षा के विकास पर होना चाहिए, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद और विकास की बुलंदियों को छू लेने के दावों के बावजूद देश ने कभी भी सकल घरेलू उत्पाद में से छह फीसद शिक्षा पर खर्च नहीं किया। हमेशा यह खर्च आंकड़ों में दिखाया जाता है, फीसद में नहीं, ताकि आबादी के लिहाज से तेजी से बढ़ते हुए देश में शिक्षा में बदलाव की धीमी गति को लेकर कोई उलझन पैदा न हो। हम शिक्षा के विकास में कृत्रिम मेधा के जरिए विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता



नैतिक, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके अलावा यह समावेशी और मितव्ययी हो, लेकिन सच तो यह है कि मितव्यय के नाम पर धन का आबंटन अब भी कम है, लेकिन न तो यह समावेशी हो सका है और न ही वहनीय। सवाल यह है कि अगर

उच्च शिक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी कला और साहित्य क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध की रुचि कम ही नजर आती है। हम कृत्रिम मेधा से नवाचार की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा शोध इस क्षेत्र की बुलंदियों की ओर जाता नहीं दिखा रहा। सवाल है कि कृत्रिम मेधा से नवाचार के लिए देश में कितने प्रशिक्षण संस्थान बनाए गए हैं। कितने शिक्षकों को हमने नई शिक्षा विधि में निपुण बनाया है? पुरानी नौकरियाँ अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि दफ्तरों में सब काम कागज रहित हो चुके हैं। हालाँकि अब भी अधिकतर संस्थानों में नौकरियों का वही पुराना ढर्रा है। दूसरी ओर चिकित्सा और इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ अब युवा पीढ़ी के लिए अंतिम विकल्प नहीं रह गई हैं।

समावेशी, रोजगारपरक और अन्वेषणपूर्ण शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना है, तो इसके लिए उद्यम कहाँ है? अगर आज भी यह रफ्तार

आती है कि भारत में हजारों प्रारंभिक विद्यालयों में एक-एक अध्यापक कई कक्षाओं को संभाल रहे हैं, तो शिक्षा में नई तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टि को आत्मसात करने का लक्ष्य कब पूरा होगा? पंजाब को ही लें, आज भी यहाँ अधिकतर छात्र कला संकायों की ओर जा रहे हैं। जबकि नई शिक्षा नीति यह कहती है कि शुरू से लेकर उच्च स्तर तक नई पीढ़ी कला और साहित्य के साथ-साथ विज्ञान एवं तकनीक का भी अध्ययन करे।

दूसरी ओर आलम यह है कि स्कूलों में दाखिले का फीसद ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन दसवीं तक आते-आते विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसकी वजह है- परिवारों की आर्थिक असुरक्षा और रोजगार की अनिश्चितता। वहीं देश की युवा पीढ़ी में काम करने की इच्छा लगातार घट रही है, तो इसका कारण उदरता से बांटी गई रेवेडियाँ भी हैं। अजब विडवना है कि एक ओर देश आर्थिक शक्ति बनता दिख रहा है और हम भविष्य में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा कर रहे हैं। आजादी के शतकीय महोत्सव 2047 तक हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। दूसरी ओर युवा पीढ़ी को अनुकंपा के जरिए धीरे-धीरे रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे विरोधाभास नहीं तो और क्या कहा जा सकता है।

उच्च शिक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी कला और साहित्य क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध की प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही। हम कृत्रिम मेधा से नवाचार की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा शोध इस क्षेत्र की बुलंदियों की ओर जाता नहीं दिख रहा। हम कृत्रिम मेधा से नवाचार की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन सवाल है कि कितने प्रशिक्षण संस्थान हमने इसके लिए बनाए हैं। कितने अध्यापकों को हमने नई शिक्षा विधि में निपुण बनाया है? नई शिक्षा नीति तो कहती है कि युवा पीढ़ी के प्रशिक्षण को किताबों के साथ-साथ यथार्थ से भी जोड़ा जाना चाहिए, मगर वास्तव में ऐसा हो नहीं पा रहा है। पुरानी नौकरियाँ अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि दफ्तरों में सब काम कागज रहित होता जा रहा है। हालाँकि अब भी अधिकतर संस्थानों में नौकरियों का वही पुराना ढर्रा है। दूसरी ओर चिकित्सा और इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ अब युवा पीढ़ी के लिए अंतिम विकल्प नहीं रह गई हैं।

इसमें दोराय नहीं कि अब कृत्रिम मेधा में दक्ष पीढ़ी तैयार हो रही है। यही लक्ष्य भी होना चाहिए। मगर अभी तक इसमें नवाचार सतही स्तर पर ही दिखाई देता है। पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं दिख रहा और न ही इस दिशा में पुस्तकें लिखी जा रही हैं। अध्यापन विधि भी नहीं बदल रही। जबकि यथार्थ के धरातल पर नई पीढ़ी को खड़ा करना नई शिक्षा नीति का लक्ष्य होना चाहिए। फिलहाल इस बारे में दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यह वास्तविक रूप से कहीं गतिमान नजर नहीं आता। अगर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर समावेशी विकास के लिए दरवाजे खोलने हैं, तो समावेशी शिक्षण होना चाहिए। इस पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। कृत्रिम मेधा के उपयोग में आगे बढ़ने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हमारी उत्पादन प्रक्रिया में इसके इस्तेमाल से लागत कम होती नजर नहीं आती। कृषि क्षेत्र में तो आज भी कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल न के बराबर है। समग्र शिक्षा अभियान में नवाचार का सपना सुंदर है, परंतु देश इस दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में शिक्षा को नवाचार से जोड़ने के प्रयास करने होंगे।

